चीनी निर्यात नीति घोषित करने का केंद्र सरकार से आग्रह

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली: आगामी चीनी वर्ष 2022-23 का पेराई सीजन एक अक्टूबर से चालू होने से पहले चीनी उद्योग ने चीनी की निर्यात नीति घोषित करने की मांग की है। इससे चीनी मिलों को विदेशी बाजार में वायदा सौदे करने का मौका मिलेगा। इससे ना केवल चीनी मिलों को अच्छा लाभ मिलेगा बल्कि गन्ना किसानों के भुगतान में सहूलियत होगी। नए सीजन में घरेलू जरूरतों के मुकाबले अतिरिक्त चीनी उत्पादन के मद्देनजर चीनी उद्योग ने केंद्र से 80 लाख टन चीनी निर्यात की अनुमति मांगी है। इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन के अध्यक्ष आदित्य झुनझुनवाला ने इस बाबत खाद्य व उपभोक्ता मामले मंत्री पीयूष गोयल से आग्रह किया है।

वर्ष 2021-22 के मार्केटिंग सीजन में सरकार ने 112 लाख टन चीनी निर्यात की छूट दी थी। चीनी मिलों ने सितंबर में खत्म हो रहे सीजन से पहले इतनी बड़ी मात्रा में चीनी का निर्यात पूरा भी कर दिया है। विश्व

- **चीनी उद्योग ने 80 लाख टन चीनी निर्यात की मांगी अनुमति**
- **मिलों को अच्छी कीमत मिले तो गन्ना किसानों के भुगतान में सहूलियत**

जिंस बाजार में चीनी की मांग और आपूर्ति की स्थिति और घरेलू बाजार में मूल्य को देखते हुए केंद्र सरकार ने चीनी निर्यात पर मात्रात्मक प्रतिबंध लगाते हुए इसे 100 लाख टन पर रोक दिया था। हालांकि बाद में चीनी उद्योग की मांग और अतिरिक्त घरेलू स्टाक के मद्देनजर सरकार ने 12 लाख टन चीनी के अतिरिक्त निर्यात की अनुमति दे दी। वैश्विक मांग के चलते चालू सीजन (अक्तूबर से सितंबर) के दौरान कुल 112 लाख टन चीनी का निर्यात हो चुका है।